IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में कोविड–19 महामारी के दौरान गैर सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका:

एक समाजषास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 राजेष कुमार त्रिपाठी
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर समाजषास्त्र
गोविन्द बल्लभ पंत महाविद्यालय,
कछला– बदायूँ उ0प्र0– 243636

सारांष–

प्रस्तुत शोध का मूल उद्देष्य भारत में कोविड–19 महामारी के दौरान गैरसरकारी संगठनों की भूमिका का एक समाजाषास्त्रीय विश्लेषण करना है। वस्तुतः गैर सरकारी संगठनों की स्थापना भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1862 के अन्तर्गत किया जाता है, जिनका मूल कार्य आम लोगों को बुनियादी सेवाएं – जैसे गरीबी उन्मूलन, मानवाधिकार, षिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा आदि से सम्बन्धित मामलों पर सेवाएँ उपलब्ध करवाना है। जिसके लिए वे सरकार और आम नागरिकों के बीच एक चेन का भी कार्य करते हैं। इसके लिए इन्हें कई गैर सरकारी संस्थाओं, सरकार और अर्न्तराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त भी प्राप्त होता है। अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो भारत में लगभग 31 लाख पंजीकृत और 1.87 के लगभग सक्रिय गैरसरकारी संगठन थे। (अक्टूबर 2023 के एक आंकड़े के अनुसार।'[1] कोविड के दौरान जहाँ कई गैरसरकारी संगठनों ने जमीनी स्तर पर प्रकार्यात्मक भूमिका का निर्वहन किया जैसे मिषन आक्सीजन, गौतम गंभीर फाउंडेषन, चिक्का फाउंडेषन, अक्षयपात्र फाउंडेषन आदि। वहीं दूसरी तरफ कुछ गैर सरकारी संगठन सिर्फ फोटो सेषन तक ही समित रहे और कई तो एकदम से गायब थे। ऐसे में उनकी प्रकार्यात्मकता और औचित्य पर कई सवाल खड़े होते हैं।

लेकिन ऐसे में आवष्यकता इस बात की है कि सिर्फ संख्या बढ़ाने से नहीं बल्कि इस प्रकार के गैरसरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करते समय उनकी सोषल आडिटिंग के साथ अनुषासन भी तय करना होगा। इस संदर्भ में सरकार को एक दीर्घकालिक रणनीति बनाते हुए स्थानीय स्तर भी उसे मूर्त रूप देना होगा।

भूमिका–

एन.जी.ओ. शब्द का पहला प्रयोग 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय किया गया। 27 फरवरी को एन.जी.ओ. दिवस मनाया जाता है। इस संगठन का मूल मकसद समाज के कमजोर और जरूरतमंद

लोगों की मदद करना है। सम्प्रति यह कहा जा सकता है कि ये समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 1862 के अन्तर्गत इनका पंजीकरण किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठन के लिए कम से कम सात सदस्य जो अलग–अलग राज्यों से हो। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर निदेषक और अन्य सदस्य होते हैं। ये एन.जी.ओ. अपने उद्देष्यों के अनुरूप अलग–2 प्रकार के होते हैं। जैसे– आपरेषनल एडवोकेसी, समुदाय आधारित, राज्यव्यापी, राष्ट्रीय आदि।

अक्टूबर 2023 के एक सरकारी आंकड़े के अनुसार वैसे तो 33 लाख पंजीकृत गैर सरकारी संगठन हैं लेकिन उसमें से लगभग 1.87 लाख ही सक्रिय रूप से कार्यरत देखे जा सकते हैं, जो सम्पूर्ण पंजीकृत संख्या का मात्र 5.6 प्रतिषत है। कोविड–19 महामाहरी के दौरान इन 5.6 प्रतिषत तथा–कथित गैर सरकारी संगठनों में से भी अधिकांष नदारद थे, कुछ फोटोसेषन तक ही सीमित थे, यद्यपि कुछ गैर सरकारी संगठनां ने जमीनी स्तर पर आम लोगों के लिए बिना किसी किसी भेदभाव के बढ़–चढ़कर कार्य किया जो उनकी प्रकार्यात्मकता को स्थापित करता है। कोविड–19 एक विषाणु जनित रोग है, जो अपनी उच्च संक्रामकता दर के कारण दिसम्बर –2019 में चीन के बुहान शहर से निकलकर 11 मार्च, 2020 तक देखते ही देखते वैष्विक स्तर पर महामारी का रूप धारण कर लिया। प्रस्तुत शोध पत्र में इन गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रकार्यात्मक और गैर प्रकार्यात्मक पहलुओं की समाजिक पड़ताल करने का प्रयास किया जाएगा।

'**कोविड–19** महामहारी के दौरान कुछ गैर सरकारी संगठनों को छोड़ दिया जाए तो जमीनी धरातल पर इनकी उपस्थिति चिंताजनक रही। कई अवसर ऐसे आए जब इनकी सबसे अधिक आवष्यकता थी, चाहे वह लाकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने का रहा हो या जब दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन एवम् वैंटीलेटर के लिए सड़कों पर दौड़ती लाखों की भीड़ इन सभी अवसरों पर ये सिर्फ फोटोग्राफी कराते नजर आए। इतना ही नहीं आम नागरिकों के द्वारा भी स्वास्थ्यकर्मियों के विरूद्ध किया जा रहा व्यवहार आधुनिक भारत के विपरीत पिछड़े भारत को दर्षा रहा था।'[2]

वस्तुतः कोविड–19 महामारी के दौरान इन गैर सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि ये ऐसे संगठन थे जिन्हें गैर लाभकारी उद्देष्यों के लिए मानवता के कल्याण को समर्पित होना चाहिए था। यद्यपि इनकी भूमिका ने मानव समाज की कई विद्रूपताओं को भी उजागर कर दिया।

'वहीं वैष्विक स्तर पर कोविड–19 महामारी के दौरान युनेस्को जैसी संस्थाओं ने कई राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के गैरसरकारी संगठनों के साथ मिलकर मीडिया नेटवर्क बनाया, जिसका मुख्य उद्देष्य गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की मदद करना था।'[3]

साहित्य सर्वेक्षण–

शोधार्थी अपने शोध कार्य को व्यापकता प्रदान करने के लिए निम्न पुस्तकों, समाचार पत्रों, बेवसाइटों का सहारा लेने का प्रयास किया है जो निम्न हैं–

'**चौधरी.आर. पु. कोविड–19 पेंडमिक–2020** मेंटल हेल्थ चैलेंज ऑफ इंटरनल माइग्रेंट वर्कर ऑफ इंडिया (एषियन जर्नल ऑफ साइक्रिटी में प्रकाषत चौधरी आर. 2020) का एक शोध–पत्र है। बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लगाया गया और अप्रवासी मजदूरों को इसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा उस पर प्रकाष डाला गया है।'[4]

'**व्हाई द लाकडॉउन उन हार्डर ऑन सिंगन वूमेन**[5] यह 9 अगस्त 2020 में प्रकाषित एक आर्टिकल का अंष है। इस आर्टिकल में कोविड के दौरान एक अकेली महिला की चुनौतियों की चर्चा की गयी है।'[5]

हैरिबैंक माइकल पु0 **द केस ऑफ एनजीओज** इन स्लोवाकिया ड्यूरिंग द कोविड–19 पेंडमिक– इस पुस्तक के लेखक हैं।

स्विडनोवा मारिया मरे– पु0 नान गर्वनमेंटल आर्गनाइजेषन रोल एण्ड परफार्मेंस इन टूरवुलेंट टाइम्स–2024। इस पुस्तक में लेखक ने गैरसरकारी संगठनों की शासन में भागीदारी पर प्रकाष डाला है।

उपरोक्त साहित्य सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि कोविड–19 महामारी के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर तो कई अध्ययन हुए हैं जबकि कोविड–19 के दौरान गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं। विषेष रूप से भारत में। शोधार्थी का यह शोध–पत्र इसी कमी की पूर्ति की दिषा में एक विनम्र प्रयास है।

शोध–प्रविधि एवम् अध्ययन क्षेत्र–

समस्या कथन–प्रस्तुत अनुसंधान की समस्या हेतु इसे निम्नवत् शीर्षकबद्ध किया गया है–

''कोविड–19 महामारी के दौरान गैर सरकारी संगठनों की भूमिका : एक समाजषास्त्रीय विष्लेषण''

शोध समस्या–

कोविड–19 महामारी के दौरान के शोधार्थी के स्वयं के अनुभवों एवम् साहित्य सर्वेक्षण में निम्न समस्या को अनुभव किया–

कोविड–19 महामारी के दौरान भारत में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका पर शोध–कार्य नहीं हुए हैं।

अध्ययन उद्देष्य–

कोविड–19 महामारी के दौरान गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का पता लगाना।

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना का प्रयोग किया है। इस प्ररचना का उद्देष्य किसी समस्या के सम्बन्ध के पूर्ण यथार्थ एवम् विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है।

प्राक्कल्पना– प्रस्तुत शोध–पत्र में निम्न प्रक्कल्पना प्रस्तावित की गयी है–

कोविड–19 के दौरान गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

अध्ययन क्षेत्र– अध्ययन की सुविधा एवम् उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेष के अम्बेडकर नगर जनपद को शोध स्थल के रूप में चुना गया है।

अध्ययन क्षेत्र परिचय–

अम्बेडकर नगर जनपद का निर्माण 29 सितम्बर 1995 को हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 2397888 है जोकि 2520 किमी0 में फैला है। इस जिले की लगभग 90 प्रतिषत आबादी गाँवों में रहती है। इस जिले में कुल 9 विकासखण्ड हैं।

समग्र–इसके अन्तर्गत शोधार्थी ने अम्बेडकरनगर जनपद की 1783309 केवल साक्षर जनसंख्या को शामिल किया है। जो कुल जनसंख्या 74.36 प्रतिषत है।

प्रतिदर्ष/निदर्ष– प्रस्तुत शोध शोधपत्र में निदर्ष के रूप में समग्र का लगभग .0055 अर्थात् 199 उत्तरदाताओं का चयन सभी 9 विकासखण्डों से निदर्षन की उपयुक्त विधि से किया गया है।

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने दो चरणों में निदर्षन की प्रक्रिया को अपनाया प्रथम चरण में उद्देष्यपूर्ण निदर्षन द्वितीय चरण में दैव निदर्षन के माध्यम से किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत–

प्रस्तुत शोध पत्र में सूचना के द्वितीयक स्रोत के रूप में पुस्तकों, सरकारी रिपोर्ट, समाचार–पत्र पत्रिकाओं एवं शोधग्रंथ तथा बेवसाइटों का प्रयोगकिया गया है।

- ''वालंटरी एक्षन नेटवर्क इंडिया'' ने अपनी एक रिपोर्ट (स्वैच्छिक क्षेत्र में पर राष्ट्रीय नीति अध्ययन) में कहा कि – भारत जैसे देष्या में एन0जी0ओज सरकार और देष की आबादी के बीच खाई को पाटते हैं।
- नीति आयोग ने भी 90 हजार से अधिक गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क किया।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन संगठनों की भूमिका सराहना किया।
- मार्च 2020 में जब कोविड–19 महामारी पर अंकुष लगाने के लिए लाकडाउन लागू हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गैरसरकारी संगठनों से वंचितों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, चिकित्सा और सुरक्षात्मक गियर की आपूर्ति, सोषल डिस्टेंसिंग पर जागरूकता अभियान में सहायता की अपील की।
- भारत में भी कई गैर सरकारी संगठन अपनी प्रकार्यात्मक भूमिका के लिए चर्चित हुए। जैसे– मिषन आक्सीजन, गौतम गंभीर फाउंडेषन, चिक्का फाउंडेषन, खाना चाहिए, अक्षयपात्र फाउंडेषन, दूर से खाना खिलाना।

शोधार्थी ने अपने अध्ययनक्षेत्र अम्बेडकर नगर जनपद के पंजीकृत गैरसरकारी संगठनों जैसे आदर्ष कलयाणकारी समिति नागपुर–जलालपुर, अलनासिर रिसर्च एउण्ड बेलफेयर सोसाइटी, अस्लामवालेकुम सेवा संस्थान की भूमिका को सतही पाया क्योंकि ये सभी कोविड–19 के दौरान जमीनी धरातल से पूरी तरह से गायब थे। अगर इनमें से कुछ जिंदा थे तो सिर्फ फोटो सेषन तक ही सीमित थे।

वहीं सूचना के प्राथमिक स्रोत के रूप में साक्षात्कार अनुसूची द्वारा 199 उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तर महत्वपूर्ण थे।

प्रदत्तों का सारणीयन एवम् विष्लेषण–

द्वितीयक सूचना के स्रोतों से पता चलता है कि इन गैर सरकारी संगठनोंकी भूमिका काफी हद तक प्रकार्यात्मक थी। जबकि यदि सूचना के प्राथमिक स्रोतों के रूप में साक्षात्कार अनुसूची को देखा जाए तो इससे प्राप्त जानकारियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है।

साक्षात्कार अनुसूची प्रष्न सं0 (1)

कोविड–19 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की कार्यषैली से आप संतुष्ट हैं– हाँ/नहीं।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन क्षेत्र अम्बेडकरनगर के 1999 उत्तरदाताओं से उपरोक्त साक्षात्कार अनुसूची के प्रष्न पर निम्न रूप में प्रतिक्रिया प्राप्त किया–

सारणी सं0 1

क्रमांक	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का :
1	हाँ	84	42.21:
2	नहीं	115	57.79:

उपरोक्त सारणी संख्या 1 से स्पष्ट है कि 199 उत्तरदाताओं में से सिर्फ 84 उत्तरदाता जो कुल उत्तरदाताओं की संख्या 42.2: है, गैरसरकारी संगठनों की कार्यषैली से संतुष्ट थे जबकि वहीं 115 उत्तरदाता जो कि कुल उत्तरदाओं की संख्या का 57.79: थे, ने गैरसरकारी संगठनोंकी कार्यषैली से असंतुष्टि दर्षाया।

साक्षात्कार अनुसूची प्रष्न संख्या–2

कोविड महामारी के दौरान कार्य करने वाले किसी स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन का नाम जानते हैं– हाँ/नहीं।

सारणी संख्या 2

क्रमांक	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का :
1	हाँ	30	15.1:
2	नहीं	169	84.9:

उपरोक्त्त सारणी संख्या 2 से स्पष्ट है कि शोधार्थी के अध्ययनक्षेत्र अम्बेडकरनगर के 199 उत्तरदाताओं में से 169 उत्तरदाताओं ने माना कि वे किसी ऐसे गैर सरकारी संगठन का नाम भी नहीं जानते जो कोविड–19 के दौरान स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहे हों। जोकि कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 84.9: है। जबकि 199 में से मात्र 30 उत्तरदाताओं की संख्या 15.1: थे, ने माना कि उन्होंने कोविड के दौरान कार्य करने वाले कुछ गैर सरकारी संगठनों का नाम जानते हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की कार्यषैली से संतुष्ट हैं– हाँ/नहीं।

सारणी संख्या 3

क्रमांक	उत्तरदाताओं के विचार	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का :
1	हाँ	14	7.03:
2	नहीं	185	92.96:

उपरोक्त सारणी संख्या 3 से स्पष्ट है कि शोधार्थी के अध्ययन क्षेत्र अम्बेडकरनगर जनपद के 199 उत्तरदाताओं में से सिर्फ 14 उत्तरदाता जोकि कुल उत्तरदाताओं की संख्या का मात्र 7.03: है, जो कोविड के दौरान गैर सरकारी संगठनों की भूमिका से संतुष्टि दर्षाया जबकि उत्तरदाताओं की कुल संख्या 199 में से 185

उत्तरदाता जो कि कुल उत्तरदाताओं की संख्या का 92.96ः थे, ने माना कि कोविड–19 महामारी के दौरान गैर सरकारी संगठनों की भूमिका सही नहीं थी।

निष्कर्ष एवं सुझाव–

सारणी संख्या 1 एवं उसके प्रदत्तों के विष्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना कि राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों की कार्यषैली से लोग संतुष्ट नहीं थे जबकि वहीं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चता है कि इसके बावजूद कुछ गैर सरकारी संगठनां की भूमिका प्रकार्यात्मक थी लेकिन ऐसे सुंगठनों की संख्या सीमित थी।

सारणी संख्या 2 एवमं उसके प्रदत्तों से विष्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांष उत्तरदाताओं को किसी ऐसे गैर सरकारी संगठन की जानकारी ही नहीं है जा`उनके क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सक्रिय हो।

सारणी संख्या 3 एवं उसके प्रदत्तों के विष्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांष उत्तरदाता कोविड–19 महामारी के दौरान गैर सरकारी संगठनों की कार्यषैली से संतुष्ट नहीं हैं। यद्यपि एक सीमित वर्ग ऐसा भी है जो इनकी कार्यषैली से संतुष्ट है। जिसका समाजषास्त्रीय निर्वचन यह कि स्थानीय स्तर पर ये गैर सरकारी संगठन जनआकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे अर्थात् उनकी प्रकार्यात्मकता संदिग्ध थी।

प्रकल्पना परीक्षण– एकत्रित किए गये प्रदत्तों के विष्लेषण के आधार पर प्रक्ल्पना की जांच आनुभाविक प्रविधि के अनुसार की गई है, जो निम्नवत् है–

प्राक्कल्पना–

कोविड–19 महामारी के दौरान गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सारणी संख्या 1, 2, 3 एवं सूचना के प्राथमिक स्रोतों के विष्लेषण एवं निष्कर्षों से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्राक्कल्पना असत्य साबित हुई।

सुझाव–

1. कोविड–19 जैसी महामारी या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर पर एक स्थायी प्रभावी तंत्र का विकास करना होगा।
2. गैर सरकारी संगठनों की सोषल आडिट के पष्चात् ही उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।
3. असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी तंत्र का विकास किया जाए।
4. कोविड–19 महामहारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी स्थानीय प्रषासन द्वारा संरक्षण प्रदान करते हुए उनके सदस्यों को प्रषिक्षित किया जाए।

प्रस्तुत शोध–पत्र शोधार्थी की सामाजिक, वैषयिक एवं आर्थिक सीमाओं के अन्तर्गत ही है जो कि भविष्य के शोधकर्त्ताओं को उपरोक्त सीमा के विस्तार द्वारा अवष्य एक रोडमैप प्रदान करेगा।

संदर्भ–

1. ीजजचरू्ण प्दकपछछळेव्बवउध्छळेम्बजपवद 4चउ 26 डंतबी 2025
2. कोविड–19 महामारी का समाज पर प्रभाव : एक समाजषास्त्रीय विष्लेषण शोध–प्रबन्ध– राजेष कुमार त्रिपाठी– डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विष्वविद्यालय, 2024 पेज नं0 215
3. उपरोक्त– पेज नं0 217

4. चौधरी आर. : कोविड–19 पेंडमिक मेंटल हेल्थ चैलेंज ऑफ इंटरनल माइग्रेंट वर्कर ऑफ इंडिया शोध–पत्र 2020 एषियन जर्नल ऑफ साइकिट्री।
5. व्हाई द लॉकडाउन इन हार्डर ऑन सिंगल वूमेन आर्टिकल टाइम्स ऑफ इण्डिया 9 अगस्त 2020

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation